

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दवि्यांगता अधिकारों को मूल अधिकार माना जाना

प्रलिमि्स के लिये:

RPwD अधनियिम 2016, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधनियिम 2017, PM-DAKSH (दिव्यांग कौशल विकास और पुनर्वास योजना), सुगम्य भारत अभियान, दीनदयाल दिवयांग पुनर्वास योजना, दिवयांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशपि

मेन्स के लिये:

भारत में दिव्यांगता अधिकार, चुनौतियाँ, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के उपाय।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि**दृष्टिबाधित उम्मीदवार** न्यायिक सेवा परीक्<mark>षाओं में भाग</mark> ले स<mark>कते</mark> हैं तथा इस बात पर बल दिया है कि<mark>दिव्यांगजन</mark> अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 के तहत **दिवयांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार** को मौलिक अधिकार माना जाना चाहिये।

न्यायिक सेवाओं में दिव्यांगता अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय है?

- भेदभावपूर्ण प्रावधानों को समाप्त करना: हाल ही में यह निर्णय मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा नियम, 1994 एवं राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 से संबंधित याचिकाओं पर निर्णय लेते हुए दिया गया तथा इन्हें RPwD अधिनियम के साथ संरेखित किया गया।
 - ॰ <u>[?][?][?] [?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]</u>, 1994 के **नयिम 6A** को रद्द कर दिया गया क्योंकि इसमें शैक्षिक योग्यता के बावजूद दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया गया था।
- दिव्यांगता अधिकारों की मान्यता: न्यायिक सेवाओं से दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को बाहर करना संविधान में प्रदत्त समानता (अनुच्छेद 14) और भेदभाव के प्रतिषध (अनुच्छेद 15) के अधिकार का उल्लंघन है।
- सकारात्मक कार्रवाई: न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्य को परोपकार-आधारित दृष्टिकोण के बजाय अधिकार-आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिय ताकि रोज़गार तक समान पहुँच सुनिश्चित हो सके।

 - ॰ इसमें पर्याप्त संख्या में <mark>दिव्यांग</mark> उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अनुसूचित जाता/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के समान**पात्रता** मानदंडों में छूट की अनुमति दी गई।

दव्यांगजनों से संबंधति ऐतिहासिक मामले

भारत में दिव्यांगजनों की स्थिति क्या है?

- 2011 की जनगणना के अनुसार, दिव्यांगजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 2.21% (2.68 करोड़) है।
 - RPwD अधिनियम, 2016 के अनुसार, दिव्यांगता के 21 मान्यता प्राप्त प्रकार हैं, जिनमें दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मूक दिव्यांगता, बौद्धिक नि:शक्तता, बहु नि:शक्तता, मानसिक मंदता और बौनापन आदि शामिल हैं।
- दिवयांगजनों के लिये संवैधानिक प्रावधान:
 - ॰ मौलकि अधकार: <u>अनुचछेद 14, अनुचछेद 19</u> और <u>अनुचछेद 21।</u>
 - DPSP: अनुचछेद 41 (बेरोज़गारी, वृद्धावस्था, बीमारी और दिवयांगता के मामलों में सारवजनिक सहायता का समर्थन करता है)।
- पंचायतों और नगर पालकाओं की ज़िम्मेदारियाँ:
 - ॰ 11वीं अनुसूची: दिव्यांगजनों सहित सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रति करती है (अनुच्छेद 243-G की प्रविष्टि 26)।
 - ॰ **12 वीं अनुसूची:** दवि्यांगजनों सहित कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है (अनुच्छेद 243-W की प्रविष्टि 9)।
- दिव्यांगता अधिकार से संबंधित कानून:
 - RPwD अधिनियिम, 2016: इसका उद्देश्य समान अवसर सुनिश्चित करना, अधिकारों की रक्षा करना और दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाना है।
- राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियिम, 1999: इस अधिनियिम के द्वारा अन्य मामलों के अलावा ऑटिज्मि, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु नि:शक्तताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतू एक राष्ट्रीय निकाय की स्थापना की गई।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017: यह अधिनियम मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करता है।

भारत में दिव्यांगजनों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- सामाजिक बाधाएँ: दिव्यांगजनों को अक्सर रोज़गार, शिक्षा और पर्याप्त आय प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अपने अधिकारों का पूर्णतः प्रयोग करने में बाधा उत्पन्न होती है।
 - ॰ पूर्वाग्रह, भेदभाव, भय और रूढ़िवादिता सामाजिक एकीकरण में बाधा डालते <mark>है तथा</mark> बहिष्<mark>कार एवं अकेले</mark>पन के दुष्चक्र को बढ़ावा देते हैं।
- परिवहन बाधाएँ: दिव्यांगता पर विश्व रिपोर्ट के अनुसार, परिवहन प्रणालियों, निर्मित पर्यावरण में दुर्गमता, समाज में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की दिव्यांगजनों की क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से सीमित करती है।
- संचार बाधाएँ: सुनने, बोलने, पढ़ने या लिखने में अक्षम दिव्यांगजनों को गैर-मौखिक संचार कौशल की अनुपस्थिति जैसे गैर-प्रभावी संचार चैनलों के कारण प्रभावी संचार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- नीतिगित और कार्यक्रम संबंधी बाधाएँ: असुविधाजनक समय-सारिणी और सुलभ उपकरणों की कमी जैसी चुनौतियाँ आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में बाधा डालती हैं।
- अंतर्विभागीय हाशियांकरण: दिव्यांग महिलाओं को लिग और दिव्यांगता के आधार पर दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।
 - ॰ **दिव्यांग जनसंख्या का 69% हसि्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है,** जहाँ सहायक प्रौद्योगिकियों के अभाव में उन्हें अधिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये भारत की क्या पहल हैं?

- PM-DAKSH (दिवयांग कौशल विकास और पुनरवास योजना)
- स्गम्य भारत अभियान
- दीनदयाल दिवयांग पुनरवास योजना
- <u>दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण और सहायता उपकरणों की खरीद/फटिगि के लिये सहायता</u>
- दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप

आगे की राह

- प्रभावी मुख्यधारा की नीतियाँ और सेवाएँ: हितधारकों को सामान्य सार्वजनिक गतविधियों और सेवाओं में दिव्यांगजनों की समान भागीदारी सुनिश्चिति करनी चाहिये।
 - पुनर्वास और सहायता सेवाओं में अधिक निवश की आवश्यकता है। उदाहरण के लिये,व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और सफेद छड़ी जैसे सहायक उपकरण दिव्यांगों की स्वतंत्रता को बढ़ाते हैं।
- मानव संसाधन क्षमता में वृद्धिः भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) को दिव्यांगता -संबंधी सेवाओं में लगे पेशेवरों की योग्यता को प्रभावी ढंग से विनियमित करने और बढ़ाने के लिये प्रशक्षिण प्रकरिया में तेज़ी लानी चाहिये।
 - ॰ जापान के **????? ??????** में दिव्यांग कर्मचारियों को रोबोट वेटरों को दूर से नियंत्रित करने के लिये नियुक्त किया गया है, जिससे समावेशी रोज़गार के अवसर पैदा हुए हैं। भारत को दिव्यांग व्यक्तियों के लिये रोज़गार सुलभता बढ़ाने के लिये इसी तरह की प्रथाओं को अपनाना

चाहिय ।

- दिव्यांगता के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना: सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने से नकारात्मक धारणाओं को चुनौती दी जा सकती है और सामाजिक और मनोवृत्त सिंबंधी बाधाओं को तोड़ा जा सकता है।
 - ॰ शैक्षिक संस्थानों को **समावेशता और वविधिता को बढ़ावा** देना चाहिये, तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि दिव्यांग व्यक्तियों के लिये आवशयक भाषा कौशल **सकषम वयकत्तियों को भी सिखाया जाए.** जिससे समावेशी संचार को बढ़ावा मिले।
- दिव्यांगता डेटा संग्रह में सुधार: आयु, लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बेहतर डेटा संग्रह से दिव्यांगजनों के सामने आने वाली बाधाओं की समझ में सुधार होगा।

प्रश्न: दिव्यांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सार्वजनिक सेवाओं में समावेशता की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। दिव्यांग व्यक्तियों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा आगे के सुधारों के लिये उपाय सुझाइए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत लाखों दिव्यांग व्यक्तियों का घर है। कानून के अंतर्गत उन्हें क्या लाभ उपलब्ध हैं? (2011)

- 1. सरकारी सकुलों में 18 साल की उमर तक मफत सकुली शकिषा।
- 2. व्यवसाय स्थापित करने के लिये भूमि का अधिमान्य आवंटन।
- 3. सारवजनिक भवनों में रैंप।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/sc-upholds-disability-rights-as-fundamental